The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

कोयना में एल्यूमिनियम प्लांट

1295. श्री मोहन स्वरूप :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे कोयना स्थित एल्यूमिनियम प्लांट को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को, जो कि सरकारी क्षेत्र में है, सौंप देने का निर्णय तीन साल पहले किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त प्लांट द्वारा 50,000 टन एल्यूमिनियम उत्पादन करने का लक्ष्य नियत किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या लक्ष्य को पूराकरने में सफलता मिली है ; और

(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) महाराष्ट्र राज्य के कोयना प्रदेश में एक नये एल्यूमिनियम प्रद्रावक की स्थापना के लिए तेन्दुलकर उद्योग (प्रा०) लि०, बम्बई, को मार्च, सन् 1960 में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाईसेंस दिया गया था। आर्थिक व अन्य कठिनाईयों के कारण लाइसेंस प्राप्तकर्ता परियोजना पर कार्य प्रारम्भ न कर सके । लाइसेंसी की विफलता को देखकर कर सरकार ने सन् 1964 में परियोजना को सरकारी क्षेत्र में समपन्न करने का निश्चय किया इस बात को ध्यानमें रखकर कि पश्चिमी जर्मनी की फर्म मैसर्स वैरिनिगटे एल्यूमिनियम वर्क परियोजना के सरकारी क्षेत्र में होने पर आवश्यक सहायता प्रदान करेगी अन्तिम तौर पर 13 अक्टूबर 1965 को लाइसेंस वापिस ले लिया गया और परियोजना को पूर्ण करने के लिए नवम्बर, 1965 में भारत एल्यूमिनियम नाम की एक सरकारी कम्पनी बनाई गई।

(ख) निर्णय किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना की क्षमता 50,000 मीट्रिक टन टन प्रति वर्ष एल्यूमिनियम धातु की होगी ।

(ग) और (घ). परामर्श-दाताओं द्वारा दिए गए परियोजना पर आने वाली लागत के प्राक्कलनों का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन के परिणाम को दृष्टि में रख कर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेगी ।

कटनी में डीजल स्टोर में आग लगने की घटना

1296. श्री मोहन स्वरूप :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1967 को कटनी (केन्द्रीय रेलवे) स्टेशन पर डीजल के भण्डार मे भीषण आग लग जाने के कारण लाखों रुपयों की सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आग लगने के कारण क्या थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। लगभग 12 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) 19-4-67 को लगभग 21.50 बजे न्यू कटनी डीजल लोको भण्डार के प्लेटफार्म पर पड़े हुए उन बक्सों में आग देखी गयी जिन में डीजल रेल इंजनों के भारी अतिरिक्त पुर्जे पड़े हुए थे। चूंकि ये बक्स बहुत भारी थे और आकार में बहुत बड़े थे इसलिए इन्हें गोदाम में, जो पहले ही भरा हुआ था, नहीं रखा जा सका। डीजल लोको कर्मचारियों की की सहायता से डीजल लोको शेड में नियुक्त आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। कटनी आर्डीनेंस फ़ैक्टरी का फायर ब्रिगेड भी सहायता के लिए पहुंच गया और 20-4-67 को 00.30 बजे तक आग पूरी तरह से बुझा दी गयी।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रशासी अधिकारियों की जो जांच समिति नियुक्त की गयी थी वह किसी निश्चित परिणाम पर नही पहुंच पायी। इसलिए इस सम्बन्ध में आगे जांच करने के लिए यह मामला पुलिस प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है।

Production of Woollen Yarn

1297. Shri B. K. Birla: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) how Government propose to achieve the Fourth Plan target for the production of woollen/worsted yarn and fabrics;

(b) the amount of foreign exchange required to import raw materials to achieve this target;

(c) the steps proposed to be taken to work the woollen industry to its double shift capacity; and

(d) whether Government have taken any steps to evolve an Indian merino breed of sheep?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) With the steps being taken by the Department of Agriculture for improving the production of indigenous wool in quantity and quality, it is expected that increased supplies of good Indian wool will be available; as for the requirements of imported raw wool, allocations of foreign exchange will be made to the extent possible, keeping in view the country's overall foreign exchange requirements.

(b) The total foreign exchange requirements for wool on the basis of 2-shift working, would be of the order of Rs. 22 crores per year after taking into account availability of indigenous man made fibres.

(c) The number of shifts worked by the industry would depend on the availability of raw materials which in turn would depend upon the availability of foreign exchange. It is also open to the industry to use Indian wool to meet part of its raw material requirements.

(d) Breeding trials with exotic sheep for evolving superior types of sheep yielding fine wool have been in progress for some years.

Collaboration with Australia

1298. Shri Ramachandra Veerappa:
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the three day Joint Survey by the Indo-Australian Officials, the Indian team suggested some collaboration programmes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the programmes which the Australian Government have agreed to consider?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) to (c). There was no Joint Survey by the Indo-Australian officials. Presumably the reference is to the Indo-Australian consultations which were held in New Delhi on April 12th to 14th in the Ministry of External